Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 5.647, Volume 10, No. 03, July, 2020, pp. 278-282

डेयरी उद्योग एवं राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रामचन्द्र मीणा*
डॉ. आर. के. दुलार**

Lkkj

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के उपरान्त पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय पौष्टिक भोजन, आय सृजन एवं उत्पादक रोजगार का महत्वपूर्ण साधन रहा है। अच्छी संख्या में दुग्ध उत्पादक पशुओं के कारण राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, जहाँ 13.94 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 1977 के बाद डेयरी विभाग के कार्यक्रमों, सहकारी क्षेत्र, ऑपरेषन फ्लड के तीन चरण, जिला संघों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों, उत्पादक एवं अवषीतन संयंत्रों की स्थापना, पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों के हितों में सुधार की अनेकों योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के डेयरी क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। शोध सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार लगभग 60 प्रतिषत उत्पादक प्रतिदिन 6 से 12 लीटर और उससे अधिक दुग्ध का उत्पादन, 80 प्रतिषत दुग्ध उत्पादकों को 1.50 लाख से लेकर 5 लाख रूपये तक की प्रति वर्ष अतिरिक्त आय से 90 प्रतिषत उत्पादकों ने माना कि हमारी आय वृद्धि से हमनें भौतिक सम्पत्तियों का निर्माण एवं सुख सुविधाओं में वृद्धि की है। सामाजिक परिवर्तनों में 95 प्रतिषत ने षिक्षा में मध्यम व व्यापक परिवर्तन, 65 प्रतिषत ने मध्यम व व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि तथा रहन–सहन, खान–पान सामाजिक सरोकारों के आयोजन में बहुत योगदान माना है। कुछ समस्याओं के बावजूद आज भी राजस्थान में व्यापक पशुधन, कृषि, पर्याप्त मानव संसाधन और सरकारी नीतियों से दुग्ध उत्पादन, आय, रोजगार आदि की व्यापक सम्भावनाऐं हैं।

'kCnkoyh %– *ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आय सृजन, उत्पादक रोजगार, पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय।*

---

iLrkouk

प्राचीन काल से ही भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के फसल एवं पशुधन उत्पादन दो मुख्य सूचक रहे हैं। वर्तमान में भारतीय कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 17.3 प्रतिशत जीडीपी/जीवीए तथा 48.9 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। इसीलिए कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ एवं ग्रामीण जनता का आधार तथा 64 प्रतिशत जनसंख्या की जीवनदायनी मानी जाती है। कृषि औसतन एक वर्ष में 90 से 120 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है ऐसे में पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय ही शेष अवधि में आय व रोजगार का मुख्य साधन रह जाता है। इसीलिए आज देश में 12 मिलियन छोटे, सीमान्त एवं भूमिहीन किसान परिवार दुग्ध उत्पादन कार्य में संलग्न हैं, जिन्हें पौष्टिक भोजन, सहायक आय एवं उत्पादक रोजगार जैसे तीन महत्वपूर्ण लाभ सृजित हो रहे हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जहाँ वर्ष 2018–19 में 187.7 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा था, जो विश्व का 9 प्रतिशत है। इसी अवधि में देश में उत्तरप्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है, जो 23.53 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन कर रहा है, इसके बाद राजस्थान 13.94

* शोधार्थी, ई.ए.एफ.एम. विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोध पर्यवेक्षक एवं पूर्व उप–प्राचार्य, आर.एल. सहरिया राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।

मिलियन टन एवं आन्ध्रप्रदेश 12.76 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन कर दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। इसका योगदान देश की वर्ष 2019 में विद्यमान 192.49 मिलियन गाय, 109.85 मिलियन भैंसे एवं 148.88 मिलियन बकरियों को जाता है, जो दुग्ध उत्पादन के तीन मुख्य स्त्रोत हैं।

राजस्थान प्राचीनकाल से ही शुष्क प्रदेश होने के कारण कृषि के साथ–साथ विशेष रूप से थार मरूस्थल में पशुपालन एवं डेयरी, आय व रोजगार के मुख्य स्त्रोत रहे हैं। स्वतन्त्रता से पूर्व राजा–महाराजाओं, ठिकानेदारों, सेठ साहूकारों की अपनी डेयरी और गौशालायें होती थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पदमा डेयरी अजमेर मानी जाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष महत्व रहा है। राजस्थान में देश का 11.27 प्रतिशत पशुधन है। डेयरी व्यवसाय का महत्व इसीलिए है कि राज्य में वर्ष 2019 में 13.3 मिलियन गाय, 13.7 मिलियन भैंस एवं 20.84 मिलियन बकरी जैसे दुधारू पशु हैं जिनका देश की दृष्टि से क्रमशः छठा, दूसरा एवं पहला स्थान है। पशुपालन एवं इसके सहायक क्षेत्र मुख्य एवं स्वतन्त्र आर्थिक गतिविधि हैं, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत योगदान करती हैं।

राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई तथा वर्ष 1975 में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा देश में दुग्ध/श्वेत क्रान्ति लाने के ऑपरेशन फ्लड नामक एक बड़ी परियोजना का शुभारम्भ 13 जनवरी 1970 को किया, जिसकी अनुपालना में राजस्थान में भी ऑपरेशन फ्लड का शुभारम्भ किया गया, जिसके तीन चरण वर्ष 1994 तक राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशुधन, पशुपालकों तथा डेयरी व्यवसायियों के विकास में क्रान्तिकारी परिवर्तन करते रहे हैं।

वर्ष 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के तहत राजस्थान सहकारिता समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी विकास फैडरेशन की स्थापना की गई। राजस्थान में डेयरी व्यवसायों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलाने एवं विशेष तौर से शहरी उपभोक्ताओं को दुग्ध माँग के अनुसार दुग्ध आपूर्ति एक उचित मूल्य पर पोष्टिक एवं शुद्ध दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति के लिए वर्ष 1977 में सहकारी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रमों को लिया गया। इसी योजना के तहत 'अमूल' की तरज पर राज्य में राजस्थान सहकारी विकास फेडरेशन की स्थापना की गई। राजस्थान में त्रिस्तरीय संस्थागत ढाँचा तैयार किया गया, जिसमें शीर्ष स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। फेडरेशन का उद्देश्य एवं मुख्य कार्य राज्य में संचालित डेयरी विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित कर वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था करना है, ताकि दुग्ध उत्पादकों एवं दुग्ध उपभोक्ताओं को समुचित लाभ प्राप्त हो सके। द्वितीय स्तर/जिला स्तर पर जिला दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना की गई जिनका कार्य ग्राम स्तर पर संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दुग्ध संकलित करना, उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहिया करना, नवीन योजनाओं से अवगत कराकर उनका लाभ प्रदान करना तथा संयंत्रों द्वारा तैयार दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करना है। तृतीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ जिनका कार्य दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध का संग्रहण कर जिला संघों को उपलब्ध करवाना है।

डेयरी विकास कार्यक्रमों के तहत आज राज्य में आरसीडीएफ, 21 जिला दुग्ध उत्पादक संघ एवं 14,466 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त आरसीडीएफ के अधीन डेयरी, दुग्ध, दुग्ध पाउडर, पशु आहार, बीज आदि की निम्न संस्थाएँ एवं केन्द्र यथा– 17 दुग्ध उत्पादक संयंत्र, 17 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, एक टेट्रापेक संयंत्र, 6 दुग्ध पाउडर उत्पादक संयंत्र, 4 पशु आहार केन्द्र, 3 बीज उत्पादक फार्म, 2 यूरिया मोलासिस बिक्री प्लांट, फ्रोजन सीमन बैंक आदि कार्यरत हैं। आज राज्य में 8.30 लाख दुग्ध उत्पादक डेयरी विकास की सहकारिता पर आधारित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदिन राज्य में 26.07 लाख किग्रा दुग्ध का संकलन हो रहा है, जिसमें से 20.35 लाख किलोग्राम का प्रसंस्करण कर वितरित कर दिया जाता है। वर्ष 2018–19 में फेडरेशन ने 2.68 लाख मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादों का निर्माण एवं विपणन किया है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति दुग्ध उपभोग 226 ग्राम से अधिक राजस्थान में उपभोग 297 ग्राम एक विशेष उपलब्धि है।

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों से पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। जिससे दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है, साथ ही सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए फेडरेशन ने जनश्री बीमा योजना, गौरक्षक बीमा, पशु आहार उपलब्ध कराने, महिला डेयरी परियोजना, दुग्ध अक्षत बीमा, सरस सुरक्षा कवच, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा, जर्म प्लाज्म केन्द्र आदि योजनाओं से दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त सभी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक संरचना, खान–पान, वेशभूषा, रहन–सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सरोकारों का आयोजन तथा आर्थिक दृष्टि से उच्च जीवन स्तर, भौतिक सुख सुविधाओं एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि में अमूल–चूल परिवर्तन आया है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में डेयरी उद्योग के विभिन्न पक्षों का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, जो दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात करना है कि डेयरी उद्योग दुग्ध उत्पादकों एवं दुग्ध व्यावसायियों के आर्थिक व सामाजिक उन्नयन में सहायक रहा तथा यह ज्ञात करना कि सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण से दुग्ध उत्पादों का सशक्तिकरण हुआ है। यह ज्ञात करना कि दुग्ध उत्पादक को दुग्ध का उचित मूल्य एवं विपणन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

अध्ययन की परिकल्पना

किसी भी शोध परियोजना की उपयोगिता एवं औचित्य का अध्ययन करने के लिए एक सुस्पष्ट परिकल्पना की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत शोध पत्र की परिकल्पना यह है कि क्या डेयरी उद्योग का वर्तमान स्वरूप दुग्ध उत्पादों के आर्थिक व सामाजिक पहलुओं को सशक्त करने में सहायक रहा है ?

शोध पत्र का विधि तन्त्र

यह शोध पत्र अध्ययन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जिसमें सम्पूर्ण राजस्थान के डेयरी क्षेत्र के समग्र सदस्यों का एक सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। 10 वर्ष की सेम्पल आकार से राज्य के 33 जिलों की दो–दो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से 3–3 सदस्यों का चयन दैव निदर्शन विधि से कर कुल 198 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। शोध तकनीक में इन उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक समंक प्रश्नावली द्वारा सदस्यों से प्राप्त किये गये हैं, जिनका औसत एवं प्रतिशत की सामान्य सांख्यिकी विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है।

सामग्री एवं विधि

उत्तरदाताओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में आये परिवर्तन (सकारात्मक एवं नकारात्मक) का विश्लेषण करने के लिए तीन मापदण्डों (उत्तरदाताओं का जनांकिकीय विवरण, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन) के 14 सूचकों को लिया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के अनुसार 62 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक उत्तरदाता 30 से 60 वर्ष की उम्र के थे। शैक्षणिक दृष्टि से 68 प्रतिशत उत्तरदाता सैकण्डरी एवं 15 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के रहे हैं अर्थात् इस व्यवसाय में 84 प्रतिशत मध्यम श्रेणी के लोग हैं। एकल परिवार एवं उत्तराधिकार प्रथा से परिवारों का आकार एवं भू–जोत का आकार कम होता चला गया है। लगभग 86 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनकी सदस्य संख्या 6 तक है। लगभग तीन चौथाई (75 प्रतिशत) परिवारों के पास 4 हैक्टेयर तक ही भूमि है। डेयरी व्यवसाय के बढ़ने से पशुपालकों के पशुओं का आकार भी बढ़ रहा है। लगभग 94 प्रतिशत परिवारों के पास चार से ज्यादा पशुधन पाया गया था। लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं को डेयरी का लगभग 8 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रहा है।

तालिका–1 उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार

क्र.सं.	सूचक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन		
	(i) 5 लीटर तक	78	39.39
	(ii) 6 से 12 लीटर	98	49.49
	(iii) 12 लीटर से अधिक	22	11.12
	कुल	198	100.00
2.	आय प्रतिवर्ष (रूपये)		
	(i) 1.50 लाख	38	19.19
	(ii) 1.51 लाख से 3 लाख	106	53.54
	(iii) 3 लाख से अधिक	54	27.27
	कुल	198	100.00
3.	चल व अचल परिसम्पत्तियों का निर्माण		
	(i) अल्प	15	7.75
	(ii) मध्यम	158	79.80
	(iii) व्यापक	25	12.62
	कुल	198	100.00
4.	भौतिक सुख–सुविधाओं में वृद्धि		
	(i) अल्प	18	9.09
	(ii) मध्यम	121	61.11
	(iii) व्यापक	59	29.80
	कुल	198	100.00

स्त्रोत – शोध सर्वेक्षण पर आधारित

तालिका–1 के अनुसार उत्तरदाताओं के डेयरी व्यवसाय से आर्थिक स्थिति में आये क्रान्तिकारी सकारात्मक परिवर्तन का निष्कर्ष निकाला गया है। 50 प्रतिशत उत्तरदाता प्रतिदिन 6 से 12 लीटर तक दुग्ध का योगदान सहकारी डेयरी एवं निजी डेयरियों को देते हैं। लगभग 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं की डेयरी व्यवसाय से प्रतिवर्ष की आय 1.51 लाख से 5 लाख रूपये तक है। आय की दृष्टि से 93 प्रतिशत लोगों ने अपनी चल–अचल परिसम्पत्तियों का निर्माण किया है और शतप्रतिशत का यह मानना है कि उनकी सामाजिक जीवन की भौतिक सुख–सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

तालिका–2 उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति में सुधार

क्र.सं.	सूचक	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	शिक्षा का विस्तार		
	(i) अल्प	10	5.05
	(ii) मध्यम	163	82.32
	(iii) व्यापक	25	12.62
	कुल	198	100.00
2.	स्वास्थ्य वृद्धि		
	(i) अल्प	68	34.34
	(ii) मध्यम	119	60.10
	(iii) व्यापक	11	5.56
	कुल	198	100.00
3.	रहन–सहन एवं खान–पान में वृद्धि		
	(i) अल्प	27	13.63
	(ii) मध्यम	138	69.70
	(iii) व्यापक	33	16.67
	कुल	198	100.00
4.	सामाजिक आयोजनों पर प्रभाव		
	(i) अल्प	72	36.36
	(ii) मध्यम	108	54.55
	(iii) व्यापक	18	9.09
	कुल	198	100.00

स्त्रोत – शोध सर्वेक्षण पर आधारित

तालिका–2 के अनुसार डेयरी व्यवसाय से लगभग 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा में वृद्धि एवं 65 प्रतिशत ने स्वास्थ्य सुविधाओं में मध्यम एवं व्यापक स्तर में वृद्धि हुई थी। लगभग 87 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि हमारे रहन–सहन, खान–पान आदि में वृद्धि हुई। लगभग 55 प्रतिशत सामाजिक आयोजनों में भी पैसा व्यय करने लगे हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलकर आया है कि डेयरी व्यवसाय से दुग्ध उत्पादकों एवं पशुपालकों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान दिया है। उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् अध्ययन में यह भी तथ्य सामने आये हैं कि तीव्र गति से बढ़ते डेयरी व्यवसाय में उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं तथा चारे का अभाव, कम दुग्ध उत्पादकता, कम मूल्य, विपणन सुविधाओं का अभाव मुख्य समस्या रही हैं। परन्तु राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशाल पशु सम्पदा, विशाल भू–भाग, व्यापक मानव संसाधन आदि से दुग्ध उत्पादों के आय, रोजगार, उत्पादन में वृद्धि एवं उच्च जीवन स्तर की व्यापक सम्भावनाएं यहाँ आज भी विद्यमान हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- बेदी एम.एस., (1987) डेयरी डवलपमेन्ट मार्केटिंग एवं इकानोमिक ग्रोथ, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- मोदी, एच.ए., (20), डेयरी माईक्रोबॉयलोजी, आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर।
- डॉ. महेन्द्र सिंह, डॉ. वी.पी.चहल, डॉ. पी.एल.कल्ला, (2011), आधुनिक डेयरी फार्मिंग, आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर।
- राव वी.एम. (2004), इवेलवेशन ऑफ यूमन डेयरी प्राजेक्ट इन राजस्थान, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- यादव सुबे सिंह, (2006) ग्रामीण बैंकिंग एवं विकास, सबलाइन पब्लिकेशन, जयपुर।
- श्री नारायण एवं डॉ. विश्वनाथ कुमार (2011) आय के साधन, पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय, अनुशीलन पत्रिका, Vol-XXXIII नाटाणी प्रकाश, (2004) डेयरी उद्योग, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर।
- राकेश कुमार व राहुल कुमार (2018), सोसियो–इकनोमिक अपलिफ्ट थ्रू मिल्क प्रोकेक्शन इन बिहार, इण्डिया इन्टरनेशनल जरनल, सी.एम.एण्ड ए.एस. वोल्यूम–7, 2018
- वर्मा संजय, (2009), डेयरी कॉपरेटिव इन इण्डिया, सतू संकल्प 17.01.2009
- शर्मा सिरीस, (2019), कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, एण्ड साइंटिफिक एग्रीकल्चर, वॉ–3, 7 जुलाई 2019.
- आर्थिक सर्वे भारत सरकार, 2018–19, नई दिल्ली, वित्त एवं आर्थिक मन्त्रालय–2018
- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 2018–19, आर.सी.डी.एफ., जयपुर।
- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 2017–18, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

♦❐♦